

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018 — चैत्र 21, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक 3619/1129/21-ब/छ. ग./2018. — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39 सन् 1987) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति के परामर्श से छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

नियम 19 में अंक एवं शब्दों “रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख)” के स्थान पर अंक एवं शब्दों “रु. 1,50,000/- (रु. एक लाख पचास हजार)” प्रतिस्थापित किया जाय.

No. 3619/1129/21-B/C. G./2018 — In exercise of the powers conferred by Section 28 of The Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court, the State Government, hereby, makes the following further amendment in The Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 2002 namely -

AMENDMENT

In Rule 19 for figures and words “Rs. 1,00,000/- (Rupees one Lac)” the figures and words “Rs. 1,50,000/- (Rupees One Lac Fifty Thousand)” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.